Inadequate funds for libraries in Delhi University

1740. SHRI GHUFRAN AZAM . Will the PRIME MINISTER be pleased to state

(a) whether Government are aware that the libraries of Delhi University especially the science libraries are being gradually asphyxiated due to lack of funds;

(b) whether it is a fact that poor condition of the libraries has an adverse impact on the academic schedules of the students; and

(c) if so, whether Govenment propose to provide sufficient funds so that the functioning of libraries of Delhi University is improved ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF EDUCATION IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (PROF. M. G. K. MENON) (a) to (c) The University Grants Commission provides funds for development and maintenance of libraries of all the Central Universities, including Delhi University. .The exact quantum of funds provided by the Commission to different Central Universities for this purpose depends on the proposals made by the individual Univerities and the availability of funds with the U.G.C. The Commission is providing about Rs. 90.00 lakhs per annum for the maintenance of libraries of Delhi University. In addition to this, during the Seventh Plans period, the Commission has allocated development grant of Rs. 91.30 lakhs for books and journals, buildings and furniture for libraries of Delhi University.

The Commission is aware of the problem being faced by libraries of all Univeisities, including Science library of Delhi University, due to steep escalation in the cost of publications, particularly science journals and books in recent years. It is recognised that poor conditions of libraries will have an adverse impact on academic work. The U.G.C. has, however, not been able to provide additional funds due to the overall resource constraints. According to the U.G.C, the Delhi University Libraries receive more grants than libraries of other Central Universities and are comparatively better placed. New initiatives, including networking of libraries, are being worked out, so that available resources for libraries can be made more effective.

पब्लिक स्कूलों को बंद किया जाना

1741. डा० अबरार अहमद खान : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में केन्द्रीय विद्यालयों सहित कितने स्कूल हैं तथा उनमें कितने बच्चे पढ़ते हैं ; देश में बारहवीं कक्षा तक, स्नातक स्तर पर तथा स्नातकोत्तर स्तर पर पढ़ने वाले छात्रों की संख्या कितनी है और इनमें से कितने छात्र ग्रामीण तथा जनजातीय क्षेत्रों के हैं ;

(ख) क्या सरकार को यह जानकारी है कि पब्लिक स्कूल केवल अमीर बच्चों को ही शिक्षा प्रदान करके पैसा कमा रहे हैं जिससे गरीब और अमीर बच्चों के बीच एक खाई पैदा हो गई है ; यदि हां, तो क्या सरकार देश में कम से कम बारहवीं कक्षा तक के सभी बच्चों को एक समान शिक्षा देने का विचार रखती है ;

(ग) क्या सरकार इन पब्लिक स्कूलों को बंद करने और इस उद्देश्य के लिए कोई कानून बनाने का विचार रखती है ; यदि हां, तो कब तक ; और

(घ) क्या सरकार सैकेण्डरी स्तर तक की शिक्षा को मौलिक अधिकारों में सम्मिलित करने का विचार रखती है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री साथ में मानव संसाधन विकास

मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्यमंत्री का अतिरिक्त प्रभार (प्रो० एम०जो०के० मेनन) : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि पब्लिक स्कूलों द्वारा वसूल किए जाने वाले शुल्क ऊंचे हैं ।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 की अन्य बातों के साथ-साथ सरकार का इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए समीक्षा किए जाने का प्रस्ताव है कि सभी बच्चों को समान स्तर की शिक्षा सुलभ कराई जानी चाहिए ।

(ग) और (घ) केन्द्रीय सरकार ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है।

विवरण

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्कूलों की संख्या (30-9-1986 की स्थिति के अनुसार)

स्कूलों का प्रकार	स्कूलों की संख्या		कुल
	ग्रामीण	शहरी	
प्राथमिक . . .	4,75,938	53,454	5,29,392
अपर प्राथमिक . .	1,12,836	25,851	1,38,687
माध्यमिक . . .	38,720	13,488	52,208
उच्चतर माध्यमिक . .	7,225	8,273	15,498
कुल : . .	6,34,719	1,01,066	7,35,785

स्कूल शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर दाखिल छात्रों की संख्या (30-9-1986 की स्थिति के अनुसार)

शिक्षा का स्तर	नामांकन		कुल
	ग्रामीण	शहरी	
प्राथमिक स्तर . .	6,67,97,907	1,98,85,382	8,66,83,289
अपर प्राथमिक स्तर . .	1,77,95,293	94,05,363	2,72,00,656
माध्यमिक स्तर . .	64,88,568	49,86,394	1,14,74,962
उच्चतर माध्यमिक स्तर .	13,45,589	20,95,274	34,40,863
कुल : . .	9,24,27,357	3,63,72,413	12,87,99,770

डिग्री/स्नातक स्तर पर छात्रों की संख्या (30-9-1986 की स्थिति के अनुसार)

शिक्षा का स्तर	नामांकन
बी०ए०/बी०ए० (आनर्स)	14,05,396
बी०एस०सी०/बी०एस०सी० (आनर्स)	6,71,888
बी०काम/बी०काम (आनर्स)	7,70,242
बी०ई०/बी०एस०सी० (इंजी०)/बी०वास्तु०	1,82,421
बी०एड०	89,152
एम०बी०बी०एस०	78,767
कुल	31,97,866

स्नातकोत्तर स्तर पर छात्रों की संख्या (30-9-1986 को स्थिति के अनुसार)

एम०ए०	1,91,086
एम०एस०सी०	79,131
एम० काम०.	61,982
पी०एच०डी०/डी०एस०सी०/डी०फिल०	31,533
कुल	3,63,732

1986-87 में ग्रामीण क्षेत्रों में कक्षा 1 से 12 में छात्रों की कुल संख्या 9,24,27,357 थी ।

शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर अनुसूचित जाति से संबंधित छात्रों का नामांकन नीचे दिया गया है :

अनुसूचित जनजातियों से संबंधित बच्चों का नामांकन (30-9-1986 की स्थिति के अनुसार)

शिक्षा का स्तर	नामांकन
प्राथमिक स्तर	69,95,848
अपर प्राथमिक स्तर	13,77,992
माध्यमिक स्तर	4,92,708
उच्चतर माध्यमिक स्तर	92,533
कुल	89,59,081

*स्नातक स्तर पर अध्ययन कर रहे अनुसूचित जन जाति के छात्रों की संख्या
(30-9-1986 की स्थिति के अनुसार)

शिक्षा का स्तर	संख्या
बी०ए०/बी०ए० (आनर्स)	25,910
बी०एस०सी०/बी०एस०सी० (आनर्स)	4,530
बी०काम०/बी०काम० (आनर्स)	9,305
बी०ई०/बी०एस०सी० (इंजी०)/बी०वास्तु०	1,812
बी०एड०	1,841
एम०बी०बी०एस०	1,750
कुल	45,148

*स्नातकोत्तर स्तर पर अध्ययन कर रहे अनुसूचित जनजाति के छात्रों की संख्या
(30-9-1986 की स्थिति के अनुसार)

एम०ए०	2,867
एम०एस०सी०	384
एम०काम०	1,531
पी०एच० डी०/डी०एस०सी०/डी०फिल०	153
कुल	4,935

*इसमे उन कुछ राज्यों के आंकडे शामिल नहीं हैं, जिन्होंने इन्हें समय पर प्रस्तुत नहीं किया है ।

Objectives of the Eighth Five Year Plan

1742. SHRI T. R. BALU ; Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) what are the objectives of the Eighth Five Year Plan; and

(b) what amount has been allocated for achievement of those objectives ?

THE PRIME MINISTER (SHRI VISH. WANATH PRATAp SINGH); (a) The approach to the Eighth Five Year Plan is. being evolved. However, the broad areas of thrust would be strengthening the federal structure, decentralisation of authority, people's participation, a greater emphasis on the development of the rural sector, sharper focus on women's role in economic activity, and employment.,

(b) Details of allocations for achievement of these objectives would be incorporated in the Plan Document.

Right to Work in the Approach Paper

1743. SHRI SURENDRA SINGH THAKUR- Will the PRIME MINISTER be pleased to refer to answer to Unstarred Question 80 given in the Rajya Sabha on the 14th March, 1990 and state

(a) whether Government are likely to consider to give priority to right to work in the approach paper for the Eighth Five Year Plan; and

(b) if so what is the perspective plan of Government in this regard ?